



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 151 राँची, गुरुवार 3 पौष, 1937 (श०)
24 दिसम्बर, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

28 अक्टूबर, 2015

1. कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-2040, दिनांक 29 अगस्त, 2006 तथा पत्रांक-120/स0को0, दिनांक 5 मई, 2015.
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-6258, दिनांक 22 नवम्बर, 2006; पत्रांक-4468, दिनांक-21.08.2007 तथा पत्रांक-2615, दिनांक 5 मई, 2008.

संख्या-5/आरोप-1-126/2014 का. 9413--श्री बहादुर प्रसाद, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 147/03, गृह जिला- गया), के निदेशक (निगरानी), झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद्, राँची के पद पर कार्यावधि से संबंधित आरोप कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-2040, दिनांक 29 अगस्त, 2006 द्वारा प्रपत्र-'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया है।

प्रपत्र- 'क' में इनके विरुद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैं:-

आरोप सं० 1. आप अपने पदस्थापन काल में झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद् अंतर्गत बाजार समितियों के लिये 'बाजार पर्यवेक्षकों' के 40 पदों (वेतनमान 4500-7000) की नियुक्ति हेतु नियुक्ति प्रक्रिया के सभी स्तरों पर वर्ष 2005 में सम्मिलित रहे हैं। 'बाजार पर्यवेक्षकों' की गंभीर अनियमितताओं में आपकी सहभागिता स्पष्ट रूप से प्रकाश में आयी है।

आरोप सं० 2. झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद् के अध्यक्ष श्री छत्रु महतो(माननीय स०वि०स०) से प्राप्त परिवाद-पत्र से स्पष्ट है कि 'बाजार पर्यवेक्षकों' की नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये गये पैनल में एक ही पदाधिकारी के कई उम्मीदवारों के नाम हैं। सफल उम्मीदवारों के पैनल प्रस्तुत करने में स्थानीय कंप्यूटर चालकों की मदद लेते हुए आपके द्वारा निजी लाभ हेतु फेरबदल किये गये, जिसकी सूचना विभाग को प्राप्त हुई है। इन अनियमितताओं में आपकी सहभागिता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। श्री प्रसाद का बेटा, भतीजा, दामाद, बेटी एवं अन्य रिश्तेदार परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये गये हैं, जिनका रोल नं० क्रमशः 00605, 08093, 04137, 05947 और 01014 है।

आरोप सं० 3. 'बाजार पर्यवेक्षकों' की परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों की प्रति दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर में प्रश्न लीक होने की बात झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद् के प्रबन्ध निदेशक के सचिव श्री अजीत शंकर ने बतायी है। आप परीक्षा संचालन हेतु पूर्ण जिम्मेदार थे, परंतु आपके द्वारा प्रश्न-पत्र लीक होने के बिन्दु पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्न-पत्र लीक होने में आपकी स्पष्ट भागीदारी रही है।

आरोप सं० 4. कर्मचारी भर्ती नियमावली, 2000 में पर्षदीय बोर्ड ने राज्य सरकार के बिना अनुमोदन प्राप्त किये ही संशोधन कर लिया। इस बिन्दु पर विधि मान्यता यह है कि झारखण्ड राज्य कृषि उपज अधिनियम की धारा-33(ठ) के अनुसार, नियमावली के अधिग्रहण के पूर्व अनुमोदन अति आवश्यक होता है परंतु आपके द्वारा पर्षद् का ध्यान इस नियम के तहत आकृष्ट नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि आपके

द्वारा जानबूझकर निजी लाभ एवं स्वार्थ पूर्ति के लिये ऐसी अनियमित कार्रवाई की गयी। इतना ही नहीं, बल्कि दिनांक-31 मार्च, 2005 को सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से विमर्श के क्रम में आपके द्वारा स्पष्ट भाषा में कहा गया कि पर्षद् को भर्ती नियमावली के गठन में राज्य सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। यह सरकार को दिग्भ्रमित करने एवं आपके स्वेच्छाचारिता, सहभागिता एवं हठधर्मिता का परिचायक है।

आरोप सं० 5. आपके द्वारा 'बाजार पर्यवेक्षकों' की नियुक्ति में कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को गुमराह करते हुए यह सूचना दी गयी कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची का अवमानना वाद सं०-149/2003 में यह आदेश दिया गया है कि 'कृषि विपणन पर्षद्, बाजार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हेतु सक्षम है, जबकि मा० उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा मूल वाद सं०-C.W.J.C. No.-9198/98 में यह आदेश दिया गया है कि पर्षद् नियुक्तियाँ कानून के अनुसार ही करेगी। इस प्रकार पुनः निजी स्वार्थ के लिये आपने पर्षद् तथा विभाग दोनों को दिग्भ्रमित किया।

आरोप सं० 6. 'बाजार पर्यवेक्षकों' की नियुक्ति में की गयी अनियमितताओं के संबंध में सरकार के आदेशानुसार श्री वैद्यनाथ प्रसाद, भा०प्र०से०, विशेष सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा गहन छानबीन एवं जाँचोपरांत विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया है, जिससे उक्त सभी आरोपों की पुष्टि होती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जाँच कार्य शुरू करने के समय पर्षद् के कार्यालय परिसर के बाहरी गेट पर ताला जड़ दिया गया था, जिसकी पुष्टि श्री महेश्वर प्रसाद सिंह, विभागीय जिप्सी चालक ने भी लिखित बयान में की है। ताला जड़ने का स्पष्ट उद्देश्य यह रहा है कि जाँच-अधिकारी के समक्ष कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सके तथा अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा सके। इस प्रकार जाँच कार्य में पूर्ण जानकारी प्राप्त कराने एवं उपलब्ध कराने में आपके द्वारा बाधा उत्पन्न की गयी।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-6258, दिनांक-22 नवम्बर, 2006 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। तदुपरांत इसके लिए स्मारित भी किया गया। श्री प्रसाद के पत्रांक-829, दिनांक 4 जून, 2007 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु कतिपय साक्ष्य अभिलेखों की माँग की गयी, जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक-4468, दिनांक-21 अगस्त, 2007 द्वारा कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड से वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, तथा इसके लिए स्मारित किया जाता रहा। इस बीच श्री प्रसाद के पत्र, दिनांक 29 फरवरी, 2008 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें दिये गये तथ्य निम्नवत् हैं:-

आरोप सं०-1. पर्यवेक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया मा० उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा अवमानना वाद संख्या-149/2003 में पारित आदेश के अनुपालन में निदेशक मंडल द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में प्रारंभ की गयी थी। अवमानना वाद में आदेश था कि झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद् नियम बनाकर तीन महीने के अन्दर नियुक्ति की प्रक्रिया समाप्त करे। इसके आलोक में निदेशक मंडल ने दिनांक 16 अगस्त, 2004 एवं 13 अक्टूबर, 2004 में पर्यवेक्षक की नियुक्ति के संबंध में निर्णय लिया था। बोर्ड की बैठक में स्वयं तत्कालीन अध्यक्ष उपस्थित थे। नियुक्ति की प्रक्रिया में केवल आरोपी पदाधिकारी ही सम्मिलित नहीं थे, बल्कि बोर्ड में पदस्थापित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी भी प्रबंध निदेशक के आदेश से सम्मिलित थे। इसलिए यह आरोप निराधार एवं तथ्य से परे है।

आरोप सं०-2. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद् ने श्री छत्रु राम महतो, तत्कालीन अध्यक्ष के परिवादों का जवाब अपने पत्रांक-08/गो०, दिनांक 15 अप्रैल, 2005 द्वारा भेज दिया था और सभी आरोपों का खंडन किया था। मेधा सूची का पैनल स्वयं प्रबंध निदेशक ने अपने देखरेख में कम्प्यूटर द्वारा तैयार कराया था। वर्णित रौल नं० किस उम्मीदवार का है, इसकी जानकारी आरोपी पदाधिकारी को नहीं है। कम्प्यूटर ऑपरेटर का चयन इनके द्वारा नहीं किया गया था। जाँच पदाधिकारी द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर के चयन के संबंध में कोई प्रमाण नहीं दिया गया है।

आरोप सं०-3. जहाँ तक प्रश्न पत्र लीक होने का प्रश्न है, इस संबंध में स्वयं प्रबंध निदेशक द्वारा C.W.J.C. No. 2653/2005 में मा० उच्च न्यायालय में दायर प्रतिशपथ पत्र की कंडिका-7 में खंडन किया गया है। इसके अलावा अध्यक्ष को भेजे गये पत्र की कंडिका-6 में भी खंडन किया गया है। परीक्षा का संचालन प्रबंध निदेशक के निर्देशन के आलोक में बोर्ड में पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जाता था, जिसकी सूची भी संलग्न की गयी है। दैनिक समाचार पत्र में परीक्षा शांतिपूर्ण सम्पन्न होने का उल्लेख है।

आरोप सं०-4. कर्मचारी भर्ती नियमावली के संबंध में अवमानना वाद संख्या-149/2003 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया था। अतः लगाया गया आरोप निराधार है।

आरोप सं०-5. C.W.J.C. No. 9198/98 के आलोक में ही अवमानना वाद संख्या-149/2003 उत्पन्न हुआ था। अवमानना वाद में ही माननीय न्यायालय का आदेश था कि तीन महीने के अन्दर नियुक्ति की प्रक्रिया समाप्त की जाय, जिसका उल्लेख ऊपर की कंडिकाओं में किया जा चुका है। अतः आरोप तथ्य से परे है।

आरोप सं०-6. जाँच के समय गेट पर ताला बंद रहने की जानकारी आरोपी पदाधिकारी को नहीं है। जाँच पदाधिकारी ने भी इसकी शिकायत प्रबंध निदेशक से नहीं की है, लेकिन जाँच के दिन प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में साक्षात्कार हो रहा था। अगर गेट पर ताला बंद था तो जाँच पदाधिकारी को इसकी शिकायत प्रबंध निदेशक से करनी चाहिए थी, जो वहाँ मौजूद थे। प्रबंध निदेशक ने अपने पत्रांक-280, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा उपायुक्त, राँची को दण्डाधिकारी एवं बल की नियुक्ति साक्षात्कार के दिन करने के लिए पत्र भेजा था। साक्षात्कार स्थल बाजार समिति पण्डरा था, जहाँ सैकड़ों ट्रक एवं व्यक्तियों का आवागमन बना रहता है। अतः यह आरोप मनगढ़ंत है।

श्री प्रसाद के विरुद्ध आरोप एवं इनके स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री प्रसाद के विरुद्ध आरोप स्पष्ट नहीं हैं तथा साक्ष्यों का अभाव

है। अतः तत्कालीन माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री द्वारा आदेश दिया गया कि कृषि विभाग से साक्ष्य की माँग हेतु कार्मिक सचिव के हस्ताक्षर से अर्द्ध सरकारी पत्र लिखा जाय ।

तदनुसार, विभागीय अ०स० पत्रांक-2615, दिनांक 5 मई, 2008 द्वारा कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड से निम्नवत् प्रतिवेदन की माँग की गयी-

(क) आरोप प्रपत्र-‘क’ के आरोप सं०-2 में निहित जिन-जिन क्रमांकों को श्री बहादुर प्रसाद का रिश्तेदार बताया गया है, उनका पूरा नाम-पता एवं श्री प्रसाद से क्या रिश्ता है एवं इसका आधार क्या है; से संबंधित विस्तृत साक्ष्य अभिलेख की स्पष्ट अभिप्रमाणित प्रति।

(ख) विपणन पर्षद्, राँची के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिये गये बयान की पठनीय एवं अभिप्रमाणित प्रति।

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-120/स०को०, दिनांक-5 मई, 2015 द्वारा वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसके आलोक में विषयगत मामले की पुनः समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर इनका स्पष्टीकरण स्वीकार करते हुए मामले को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री बहादुर प्रसाद, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, एवं अन्य संबंधितों को भेज दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
दिलीप तिर्की,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 151—50 ।